



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2017 / पौष 13, 1938

No. 02]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017/PAUSA 13, 1938

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

फा. सं. 12015/47/2016-आई टी.—रोजगार गहन वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधार संबंधी उपाय शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में परिधानों पर राज्य लेवियों की छूट की योजना अधिसूचित की गई थी। सरकार ने अब इस योजना को मेड-अप्स पर भी लागू करने का निर्णय लिया है। वस्त्र मंत्रालय छूट व्यवस्था के माध्यम से मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट का प्रावधान करने के लिए निम्नलिखित योजना अधिसूचित करता है:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1.1 यह योजना मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट योजना, 2016 कही जाएगी (इसके पश्चात इसका उल्लेख मेड-अप्स के लिए आरओएसएल योजना के रूप में उल्लेख किया जाएगा)। उक्त योजना अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होगी और उस तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

2. उद्देश्य

2.1 निर्यात उत्पादों की जीरो रेटिंग के मान्य आर्थिक सिद्धांतों और इस तथ्य को मानते हुए कि इस समय ड्रॉवैक योजना के माध्यम से केवल केंद्रीय लेवियों में ही छूट दी जाती है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सरकार केवल औसत आधार पर मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट योजना के माध्यम से ड्यूटी ड्रॉवैक योजना के अतिरिक्त राज्य लेवियों की छूट प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य मेड-अप्स के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना है जिससे मेड-अप्स के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

3. परिभाषाएं

- 3.1 निर्यात का इसके व्याकरण संबंधी रूपों और समानार्थी अभिव्यक्तियों के रूप में यह तात्पर्य है कि भारत से किसी माल को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना है।
- 3.2 मेड-अप्स के किसी निर्यातक द्वारा सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष की गई प्रविष्टि लदान बिल या निर्यात बिल होगा।
- 3.3 निर्यात किए गए मेड-अप्स का मूल्य प्रकी ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य होगा।

3.4 टेक्सटाइल्स मेड-अप्स का तात्पर्य उस माल से होगा जो ड्रॉबैक की ऑल इंडस्ट्री रेट (एआईआर) की अनुसूची के अध्याय 63 में आता है और इसमें प्रशुल्क आइटम 6308, 6309, 6310 तथा प्रशुल्क आइटम 9404 का वह माल शामिल नहीं है जिन्हें ड्रॉबैक प्रशुल्क आइटम 6304 से हटा दिया गया है।

3.5 राज्य लेवी की छूट से यह समझा जायेगा जिसमें पैकेजिंग, ईंधन, विद्युत उत्पादन पर शुल्क और यार्न से तैयार मेड-अप्स के उत्पादन के विभिन्न चरणों में यथा संचित ग्रिड पावर की खरीद पर शुल्क और प्रभार सहित इनपुट पर राज्य वीएटी/सीएसटी शामिल हो।

4. छूट की दर

4.1 भारत में विनिर्मित मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट की दरों (अनुमेय सीमा सहित) की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा गठित ड्रॉबैक समिति द्वारा की जाएगी और वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया जाएगा।

4.2 दर और छूट केवल उन निर्यातकों पर लागू होगी जिन्होंने कार्य स्थल पर महिलाओं का घैन शोषण (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम 2013 के अनुसरण में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है और यदि निर्यातक ने किसी अन्य तंत्र के तहत इन विशिष्ट राज्य लेवियों को जमा/छूट/पुनःप्राप्ति /प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है या वह दावा नहीं करेगा।

4.3 सरकार का यह अधिकार होगा कि वह संगत मूलभूत शर्तों में परिवर्तन होने के संदर्भ में दर और अधिकतम सीमा में उचित रूप से समायोजन करे।

5. छूट का दावा

5.1 आरओएसएल योजना निर्यातक के लिए बैकल्पिक है। जो निर्यातक इस योजना का विकल्प चुनता है वह आइटम स्तर पर ड्रॉबैक निर्यात संबंधी छूट का दावा करेगा जिसमें वह योजना के निवंधन और शर्तों पर अपना अंशदान और अपनी स्वीकृति देने के साथ-साथ इसमें उपर दिए गए पैरा 4.2 का अनुपालन करने की भी घोषणा करेगा। ऐसे दावे और घोषणा करने की पद्धति अलग से प्रसारित की जाएगी।

6. बजट संबंधी प्रावधान और छूट का भुगतान

6.1 वस्त्र मंत्रालय के बजट आवंटन से छूट संवितरित की जाएगी जिसमें सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके माध्यम से निर्यातकों के बैंक खातों में संवितरण के लिए ई-पीएओ, सीबीईसी में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ भुगतान की ड्रॉबैक रूटिंग लिस्ट के लिए निर्यातों को संसाधित किया जाता है। मैनुअल शिपमेंट किए जाने पर भुगतान की सूची पीएओ, सीबीईसी के माध्यम से दी जाएगी।

6.2 एफओबी मूल्य का प्रयोग कर छूट की राशि की गणना की जाएगी। अनुसूची 3 के कॉलम (4) और (5), जिसे अधिसूचित किया जा रहा है, में दर्शाई गई प्रशुल्क आइटम के लिए अधिकतम सीमा के साथ गणना के लिए छूट की सामान्य दर तब लागू की जाएगी जब एआईआर के अनंतिम सीमा शुल्क भाग के लिए दावे के साथ ब्रांड दर ड्रॉबैक के लिए दावे के तहत एआईआर ड्रॉबैक या निर्यात के लिए एआईटम का दावा किया गया हो।

6.3 माल निर्यात किए जाने के बाद तथा ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ किन्तु ड्रॉबैक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पृथक रूप से छूट के दावों पर कार्रवाई की जाएगी।

6.4 वस्त्र मंत्रालय संवितरित किए गए छूट के दावों की मासिक सूची प्राप्त करेगा ताकि योजना के पैरा 4.2 के संदर्भ में की गई घोषणा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस पर उचित रूप से नजर रखी जा सके।

7. दावाकर्ता द्वारा पुनः भुगतान/वसूली और विवाद का हल

7.1 यह छूट विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 में दी गई समय सीमा में बिक्री से प्राप्त आय की रसीद प्राप्त होने के अध्यधीनी दी जाएगी और ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में इस आधार पर ऐसी छूट कभी नहीं दी गई है। इसके अलावा ऐसा कोई कारण जिससे ड्यूटी ड्रॉबैक भी प्रभावित होती हो उसके बारे में भी छूट संबंधी इसी प्रकार का प्रभाव माना जाएगा। इन मामलों में सीबीईसी के अधिकारी, गलती से या अधिक भुगतान की गई ड्यूटी ड्रॉबैक की वापसी के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर यथा लागू प्रक्रिया को अपनाएंगे और उसकी वसूली करेंगे। विवाद संबंधी मामलों सहित ड्यूटी ड्रॉबैक के निर्णय इस योजना के तहत छूट पर यथा परिवर्तनों सहित लागू हुए माने जाएंगे और सीबीईसी के अधिकारी द्वारा तदनुसार उनकी वापसी और वसूली की जाएगी। इसके अलावा, गलत गणना करने से अधिक भुगतान की गई छूट को भी निर्यातक वापस करेगा। जहां किसी राशि का पुनः भुगतान किया जाना हो, वसूली की जानी हो

या उसे लौटाया जाना हो वहां छूट के भुगतान की तारीख से पुनः भुगतान, वसूली या लौटाये जाने की तारीख तक निर्यातक द्वारा 15% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।

- 7.2** यदि इस योजना के पैरा 4.2 की पात्रता शर्तों को पूरा करने के संबंध में निर्यातक की गलत घोषणा से वह छूट प्राप्त करता है तो वस्त्र मंत्रालय के तहत वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

8. बचत खंड

- 8.1** आरओएसएल योजना समाप्त होने पर जिन दावों का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जायेगा जबकि वसूली और विवाद समाधान तंत्र लागू होना जारी रहेगा।

डॉ. सुनील गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

F. No. 12015/47/2016-IT.—In pursuance of the decision of the Government of India to initiate measures for reforms to boost employment generation in the employment intensive textile and apparel sector, scheme for remission of State Levies on garments had been notified. The government has now decided to extend the scheme to Made-ups. The Ministry of Textiles notifies the following scheme to provide for the remission of State Levies on export of Made-ups through the mechanism of rebate:

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- 1.1.** The scheme shall be called **Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups 2016**. (hereinafter referred to as the **ROSL Scheme for Made-ups**). The said Scheme will come into operation from a date to be notified and shall remain in operation for a period of three (3) years from that date.

2. OBJECTIVE

- 2.1.** In accordance with the recognised economic principle of zero rating of export products and in recognition of the fact that at present only Central Levies are rebated by way of the drawback scheme, it has been decided that the Central Government would provide for remission of State Levies in addition to the Duty Drawback Scheme, through the Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups on an average basis only. The scheme aims to boost India's exports of Made-ups thereby augmenting investment and creation of more employment in the Made-ups sector.

3. DEFINITIONS

- 3.1.** Export with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India.
- 3.2.** Shipping Bill or Bill of Export shall be the entry made before proper officer of Customs by an exporter of Made-ups.
- 3.3.** Value in relation to exported Made-ups shall be the Free on Board (FOB) value.
- 3.4.** Textile Made-ups shall mean goods falling under chapter 63 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of drawback excluding tariff items 6308, 6309, 6310 and goods in tariff items 9404 that are excluded from drawback tariff item 6304.

3.5. Rebate of State Levies shall be understood to comprise State VAT/CST on inputs including packaging, fuel, duty on electricity generation and duties and charges on purchase of grid power, as accumulated through the stages of production from yarn to finished Made-ups.

4. RATE OF REBATE

4.1 The rates (including applicable caps) of rebate of the State Levies on export of Made-ups manufactured in India shall be recommended by the Drawback Committee constituted by the Central government and notified by the Ministry of Textiles.

4.2 The rate and rebate shall be applicable only to exporters who have constituted an Internal Complaints Committee (ICC) in pursuance of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, and if the exporter has not claimed or shall not claim credit/rebate/refund/reimbursement of these specific State Levies under any other mechanism.

4.3 The Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions.

5. CLAIM FOR REBATE

5.1. The ROSL scheme is optional for the exporter. An exporter opting for this scheme shall make claim for rebate on drawback exports at item-level signifying both his subscription to and acceptance of the terms and conditions of the Scheme as well as exporter's declaration of compliance to Para 4.2 hereinabove. The method of exercising such claim-cum-declarations shall be publicised separately.

6. BUDGETARY PROVISION AND PAYMENT OF REBATE

6.1 The rebate shall be disbursed from budgetary allocation of Ministry of Textiles using the Customs EDI System through which the exports are processed for Drawback routing list of payments with digital signature to e-PAO, CBEC for disbursal into the exporters' bank accounts. In case of manual shipments, list of payments would be routed to PAO, CBEC.

6.2 The amount of rebate shall be calculated using the FOB value. The general rate of rebate with cap for a tariff item as shown in columns (4) & (5) of Schedule 3 which is being notified shall be applied for calculation when the item has claim for AIR Drawback or export under claim for brand rate drawback with claim for provisional Customs portion of AIR.

6.3 The processing of rebate claims shall be made after the goods are exported and in parallel with Duty Drawback albeit separately after drawback is processed.

6.4 Ministry of Textiles would obtain monthly list of rebate claims disbursed to cause appropriate checks for ensuring integrity of declarations made in terms of para 4.2 of the scheme.

7. REPAYMENT BY CLAIMANT/ RECOVERY AND DISPUTE RESOLUTION

7.1 The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed on the same lines as Duty Drawback. Further, any other cause that also affects the Duty Drawback shall be deemed to have the similar effect on the rebate. In these cases, the officers of CBEC shall in any case be adopting the processes as applicable to Duty Drawback Scheme for repayment of erroneous or excess paid Duty Drawback and its recovery. The decisions with respect to Duty Drawback, including in cases of disputes, shall be deemed to apply *mutatis mutandis* to the rebate under this scheme and repayment or recovery made accordingly by the officer of CBEC. Further, the exporter shall return any over-payment of rebate arising from miscalculation. Where there is repayment, recovery or return, interest shall also be paid by exporter at the rate of fifteen per cent per annum calculated from the date of payment of rebate till the date of repayment, recovery or return.

7.2 When rebate is availed by wrong declaration of exporter regarding meeting the eligibility conditions in para 4.2 of this scheme, the action would be initiated and concluded in the individual case by the O/o Textile Commissioner under the Ministry of Textiles.

8. SAVING CLAUSE

8.1 Upon cessation of the ROSL Scheme, the unpaid claims shall be settled in accordance with the provisions of the Scheme while the recovery and dispute resolution mechanisms shall continue to be in force.

Dr. SUBRATA GUPTA, Jt. Secy.